http://www.developindiagroup.co.in/

जे.पी.एस.सी.

झारखण्ड सिविल सेवा
मुख्य परीक्षा अध्ययन सामग्री

पूर्णतः संशोधित एवं अद्यतन

भारतीय संविधान,
राजनीति एवं लोक प्रशासन

प्रश्नपत्र – IV

Prepared by
Develop India Group

https://www.developindiagroup.co.in/

PUBLISHED BY

Develop India Group

Allahabad (U.P.), India
Mobile : 08756987953
email : subscriptiondevelopindia@gmail.com
Website : https://developindiagroup.co.in/

Edition : 2019

Develop India Group Aims

We conduct Study Material Programme, All India Correspondence Courses, Test Series Programmes for various competitive exams. All things prepared by our expert faculties. Our aims to provide quality of comprehensive materials in a single place at your home according to your requirement.

Notes Prepared by

All study notes of DEVELOP INDIA GROUP prepared by our expert team and revised time to time. We have published these notes with carefully, but we can't take gaurantee for human as well as printing mistakes. If you want to give your feedback you can write us email : **subscriptiondevelopindia@gmail.com**

Terms & Conditions

If you want to buy any kind of study materials/previous year question papers, you can contact us.

Privacy Policy & Copywrite

All matter compile in this notes from various sources believed to be reliable. We published very carefully to this matter, its authors can not take guarantee the occuracy or completeness of any information published herein and neither Develop India Media Group nor its authors shall be responsible for any errors, omissions or damage arising out of use of this information.

No part of this notes may be reproduce or transemitted without the written permission of the publisher.

@ All right reserved. Refund is not available.

Note : All disputes will respect to this publication shall be subject to jurisdiction of the courts, tribunals and forums of Allahabad, India.

CORPORATE OFFICE

Develop India Media Group

Allahabad (U.P.); India
Mobile : 08756987953
emails : subscriptiondevelopindia@gmail.com,
developindiamediagroup@gmail.com
Website : https://developindiagroup.co.in/

भारतीय संविधान, राजनीतिक एवं लोक प्रशासन

भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार, विकास, विषेशताएं, संशोधन, महत्त्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना

भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार

भारतीय संविधान का निर्माण अनेक ऐतिहासिक घटनाओं पर निर्भर था। ब्रिटिश काल के दौरान विकसित लक्षणों ने संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि निर्मित की। ये लक्षण निम्नलिखित हैं :

रेग्युलेटिंग ऐक्ट, 1773

- इस ऐक्ट के तहत संसदीय नियंत्रण का आरम्भ हुआ।
- बंगाल का गवर्नर, गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल बना।
- मद्रास और बम्बई प्रेसीडेंसी बंगाल के अधीन हो गई।
- इसने भारत में केंद्रीकृत शासन प्रणाली का आरम्भ किया।
- कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश *सर एलिजाह इम्पे* बने।

पिट्स इंडिया ऐक्ट, 1784

- इस अधिनियम को रेग्युलेटिंग ऐक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पारित किया गया।
- इसके द्वारा भारतीय मामलों को ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कर दिया गया।
- कम्पनी के शासकीय निकाय अर्थात् निदेशक मंडल के ऊपर छह सदस्यीय *'नियंत्रक मंडल'* का गठन किया गया। भारत मंत्री, वित्त मंत्री, चार प्रीवी काउंसिलर सदस्यों को भारतीय मामलों का आयुक्त बनाया गया।
- पिट्स ऐक्ट की व्यवस्था 1857 तक चलती रही।

1813 का चार्टर ऐक्ट

- कम्पनी के भारत में व्यापारिक एकाधिकार (चाय को छोड़कर) को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की छूट दी गई।
- कम्पनी की वाणिज्यिक आय को क्षेत्रीय राजस्व से पृथक कर दिया गया।
- स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया।
- भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपये वार्षिक व्यय करने का प्रावधान किया गया।
- *धर्म विभाग* (एक्लीजिओस्टिकल विभाग) की स्थापना की गई। इस ऐक्ट में नीति–निदेशक तत्त्वों के बीज देखने को मिलते हैं।

1833 का चार्टर ऐक्ट

- ये ब्रिटिश भारत में केंद्रीयकरण की ओर अंतिम चरण माना जाता है। कम्पनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और वह प्रशासनिक संस्था की भूमिका निभाने लगी।
- बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने।
- गवर्नर जनरल के परिषद में एक चौथा सदस्य विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया। *लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि सदस्य* बने।
- बॉम्बे, मद्रास की सरकारों को विधायी अधिकार से वंचित कर दिया गया।
- इसमें यह प्रावधान किया गया कि केवल जन्म, जाति, वर्ग, धर्म या जन्मस्थान के आधार पर किसी को किसी पद या सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा।
- लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया और IPC, CrPC और CPC का निर्माण किया गया।
- पहली बार इस अधिनियम में भारतीय संविधान में वर्णित मूलाधिकारों के बीज देखने को मिलते हैं।

1853 का चार्टर ऐक्ट

- इस ऐक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियां पृथक की गईं।
- भारत के लिए अलग विधान परिषद की स्थापना की गई।

Develop India Group

Why should read "Develop India Group" Study Material?

डेवेलप इंडिया ग्रुप अध्ययन सामग्री को क्यों पढ़ना चाहिए?

1. Develop India Group (DIG) is India's largest complete study materials provider website. डेवेलप इंडिया ग्रुप (DIG) भारत की सबसे बड़ी अध्ययन सामग्री प्रदाता वेबसाइट है।

2. Develop India Group (DIG) prepared their study materials in the guidance of highly qualified and experience mentoring specialist. डेवेलप इंडिया ग्रुप (DIG) ने सुयोग्य और अनुभवी सलाह विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में अपनी अध्ययन सामग्री तैयार की है।

3. Develop India Group (DIG) study materials have been prepared strictly according to revised syllabus. डेवेलप इंडिया ग्रुप (DIG) अध्ययन सामग्री पूर्णतया संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार की गई है।

4. Only aim behind preparing these study materials is to provide study material to those students, who are unable to attend coaching classes in mega cities. इन अध्ययन सामग्रियों को तैयार करने का उद्देश्य केवल उन छात्रों को अध्ययन सामग्री प्रदान करना है, जो महानगरों में कोचिंग क्लासेस में भाग लेने में असमर्थ हैं।

5. All kind of facts & data in this material have been collected from authentic sources. इस सामग्री में सभी प्रकार के तथ्यों और डेटा को प्रामाणिक स्रोतों से एकत्र किया गया है।

6. All kind of data is updated in quarterly in our study notes. हमारी अध्ययन सामग्रियों में सभी प्रकार के आंकड़ों को तिमाही में अपडेट किया जाता है।

7. Develop India Group (DIG) study materials have been prepared in simple language so that student can memorize easily and better understand. डेवेलप इंडिया ग्रुप (DIG) अध्ययन सामग्री सरल भाषा में तैयार की गई है ताकि छात्र आसानी से और बेहतर ढंग से समझ सके।

8. Complete syllabus of preliminary and main exam has been covered in this study material. प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का पूरा पाठ्यक्रम इस अध्ययन सामग्री में शामिल किया गया है।

9. All important and relevant points have been highlighted in bold, underline and italic ways. बोल्ड, रेखांकन और इटैलिक तरीके से सभी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक बिंदुओं को हाइलाइट किया गया है।

10. We have prepared our study materials with trained, talented, experienced team for each subject. They are supported by subject experts. हमने प्रत्येक विषय के लिए प्रशिक्षित, प्रतिभाशाली, अनुभवी टीम के साथ और विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में अध्ययन सामग्री तैयार की है।

11. Once you will read these study materials, you will surely find 70 to 80 % questions in next coming examination. एक बार जब आप ये अध्ययन सामग्री पढ़ लेंगे, तो आपको निश्चित रूप से आने वाली परीक्षा में 70 से 80: प्रश्न मिलेंगें।

12. So BUY TODAY and secure your future. इसलिए आज ही खरीदें और अपना भविष्य सुरक्षित करें.

Call us for more details : +91 8756987953

Develop India Group

- भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया।
- विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर गवर्नर जनरल की अनुमति अनिवार्य कर दी गई तथा उसे वीटो पावर भी दी गई।
- कम्पनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए योग्यता प्रणाली को मान्यता दी गई।

1858 का भारत सरकार अधिनियम

- इसे *'ऐक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट फॉर इंडिया'* कहा गया।
- कम्पनी का शासन समाप्त किया गया और भारतीय सत्ता ब्रिटिश ताज को दे दी गई।
- भारतीय मामलों का प्रभारी ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, जिसे भारत मंत्री कहा गया। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई। भारत मंत्री (सचिव) ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था।
- गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। इस प्रकार ***लॉर्ड कैनिंग*** *भारत के अंतिम गवर्नर जनरल* और *प्रथम वायसराय* बने।

1861 का भारतीय परिषद् अधिनियम

1861 ई. में 'प्रथम भारतीय परिषद् अधिनियम' पारित किया गया। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं :

- वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया।
- वायसराय की परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों को नामित करने का अधिकार दिया गया।
- पहली बार भारतीयों को विधायी कार्यों में संलग्न किया गया।
- गवर्नर जनरल को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद् की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति दे दी गई। ये अध्यादेश अधिकाधिक 6 मास तक लागू रह सकते थे।

1892 का भारतीय परिषद अधिनियम

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं :

- इस अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधित्व प्रणाली या प्रतिनिधि सरकार की शुरुआत की।
- वार्षिक बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी गई।
- कुछ शर्तों के अधीन सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया।

भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 (मार्ले–मिंटो सुधार)

- मार्ले–मिंटो सुधार का लक्ष्य 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना तथा भारतीय राजनीति में बढ़ते हुए उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से उत्पन्न स्थिति का सामना करना था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं :
- अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई।
- साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसमें मुस्लिम सम्प्रदाय के लिए अलग निर्वाचक मंडल का निर्माण किया गया।
- सार्वजनिक महत्त्व के विषय पर बहस का अधिकार दिया गया।
- परिषद के भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया।
- इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव की परिषद तथा भारत के वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सर्वप्रथम भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। दो भारतीय के.सी. गुप्ता तथा सैय्यद हुसैन बिलग्रामी को इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त किया गया।

भारत सरकार अधिनियम, 1919 (माण्टेग्यू एवं चेम्सफोर्ड सुधार)

- यह माउंटफोर्ड योजना पर आधारित था, जिसे 1921 से भारत में लागू किया गया।
- इस अधिनियम के द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया।
- प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रांतीय सरकार के दो भाग हो गए :
  1. आरक्षित : जिसका प्रशासन गवर्नर अपने द्वारा मनोनीत सदस्यों के माध्यम से करता था।
  2. हस्तांतरित : जिसका प्रशासन गवर्नर, विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा बनी मंत्रिपरिषद की सहायता से करता था।
- स्थानीय स्वशासन प्रांतीय तथा हस्तांतरित विषय बनाया गया।
- *केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना* की गई, जिन्हें विधानसभा तथा राज्य परिषद का नाम दिया गया। केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल तीन वर्ष का था और ये पूरे भारत के लिए कानून बना सकती थी।
- *भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली* की स्थापना की गई।
- वायसराय की परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाकर तीन कर दी गई।
- महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया।
- इस अधिनियम के द्वारा *स्त्रियों को मताधिकार* दिया गया।

नेहरू रिपोर्ट

Develop India Group